राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और एक अन्य

बनाम

पन्नालाल चौधरी और एक अन्य

(सिविल अपील सं. 5070/2008)

1 जुलाई, 2015

[विक्रमजीत सेन और अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानून - सेवा से बर्खास्तगी - बर्खास्तगी का आदेश – की वेधता - राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रतिवादी-रजिस्ट्रार के खिलाफ वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं के आरोप - प्रधान और सचिव, एनआईटी द्वारा बर्खास्तगी का आदेश – चुनौती इस आधार पर कि प्रधान और सचिव एनआईटी इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए अधिकृत नहीं है क्योंकि नियमों के तहत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी), एनआईटी को बर्खास्त करने का अधिकार निहित है – अभिनिर्धारित किया गया : बीओजी द्वारा पारित प्रस्तावों से पता चलता है कि बीओजी ने प्रतिवादी के मामले की निगरानी की, निपटाया और अंततः निर्णय लिया। स्थापना के बाद से उनकी विभिन्न बैठकें हुईं और प्रधान एवं सचिव को बीओजी के अध्यक्ष के परामर्श से इससे निपटने और उचित आदेश पारित करके आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया- हालांकि प्रस्ताव में "प्रतिवादी को खारिज करने" की अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन अध्यक्ष की सलाह के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने और अध्यक्ष की सलाह के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने और संकल्प के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की अभिव्यक्ति इतनी व्यापक थी कि प्रधान और सचिव को बर्खास्तगी आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की जा सके, यदि अवसर हो तो उत्पन्न हुआ – इसके अलावा, आवेदन तथ्यों के अनुसमर्थन का कानून, प्रतिवादी को बर्खास्त करके प्रधान और सचिव द्वारा प्रयोग किए

गए अधिकार को बीओजी द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदित किया गया था, जिससे नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप एक अमान्य कार्य वैध हो गया - सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश -बीओ जैसा कि नियमों में निर्धारित है और इस प्रकार, कानूनी और उचित था और इसे बरकरार रखा गया है - उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया।

शब्द और वाक्यांश: अभिव्यक्ति "अनुमोदन" - का अर्थ।

मैक्सिम्स - "रतिहैबिटियो मैंडेटो एइक्विपैराचर" - माना गया: "किसी अधिनियम का बाद का अनुसमर्थन ऐसे कार्य को करने के लिए पूर्व प्राधिकारी के बराबर है"।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित किया : 1.1 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स-बीओजी द्वारा बिना किसी अनिश्चित शब्दों के साथ पारित प्रस्तावों को पढ़ने से पता चलता है कि बीओजी ने स्थापना के बाद से अपनी विभिन्न बैठकों में प्रतिवादी के मामले की निगरानी की, निपटाया और अंततः निर्णय लिया और प्रधान और सचिव को भी अधिकृत किया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के परामर्श से इससे निपटना और उचित आदेश पारित करके आवश्यक कार्रवाई करना। अभिव्यक्ति में "प्राधिकरण", "अध्यक्ष की सलाह के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए" और "तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने" की अभिव्यक्ति इतनी व्यापक थी कि प्रधान और सचिव को अवसर आने पर बर्खास्तगी आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई। [पैरा 30,31] [94-बी-सी; डे]

1.2 अपीलकर्ता ने सही ढंग से प्रस्तुत किया कि प्रधान और सचिव को उचित आदेश पारित करने के लिए अधिकृत करने वाले प्रस्तावों में "प्रतिवादी को बर्खास्त करने" की अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि उस समय, प्रतिवादी के खिलाफ विभागीय जांच विचाराधीन थी। इसलिए, उस समय यह ज्ञात नहीं था कि

विभागीय कार्यवाही का नतीजा क्या होगा और दूसरे, विभागीय जांच शुरू होने से पहले संकल्प में इस तरह की अभिव्यक्ति का उपयोग प्रतिवादी के खिलाफ मुद्दे को पूर्वाग्रहित करने के रूप में माना जा सकता था, इससे प्रतिवादी के प्रति बीओजी के सदस्यों के पूर्वाग्रहपूर्ण रवैये का संकेत मिलता है और अंत में संकल्प में प्रयुक्त तीन अभिव्यक्तियों ने प्रधान और सचिव को उचित आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की, जिसमें नियमों में निर्धारित बर्खास्तगी की सजा लगाने का आदेश भी शामिल था विभागीय जांच के नतीजे के आधार पर प्रतिवादी के खिलाफ और बीओजी द्वारा अंतिम मंजूरी दिए जाने के अधीन। [पैरा 32] [94-एफ-एच; 95-ए-बी]

1.3 चार संकल्पों की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बर्खास्तगी आदेश बीओजी द्वारा पारित किया गया था और प्रधान और सचिव ने केवल अपने प्राधिकरण के बल पर बीओजी के लिए और बीओजी की ओर से प्राधिकरण के बल पर बीओजी द्वारा अपने पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया । [पैरा 33] [95-डी-ई]

1.4 अभिव्यक्ति "अनुमोदन" का अर्थ है "पहले से किए गए कार्य को वैध बनाना"। यह सिद्धांत लैटिन कहावत "रतिहैबिटियो मैंडेटो एइक्विपरेटुर" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "किसी अधिनियम का बाद का अनुसमर्थन ऐसे कार्य को करने के लिए पूर्व प्राधिकारी के बराबर है।" इस प्रकार, अनुसमर्थन एक अमान्य कार्य मानता है, जिसे पूर्वव्यापी रूप से मान्य किया जाता है। अनुसमर्थन के कानून को तथ्यों पर लागू करते हुए, भले ही यह मान लिया जाए कि बर्खास्तगी का आदेश प्रधान और सचिव द्वारा पारित किया गया था, जिनके पास नियमों के तहत ऐसा आदेश पारित करने का न तो कोई अधिकार था और न ही बीओजी द्वारा उनके पक्ष में कोई प्राधिकरण दिया गया था। इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए अभी तक जब बीओजी ने अपनी बैठक में प्रतिवादी के बर्खास्तगी आदेश को पारित करने में प्रधान और सचिव की पिछली

कार्रवाइयों को मंजूरी दे दी, तो कार्यवाही में प्रतिवादी द्वारा शिकायत की गई सभी अनियमितताएं, जिसमें उसे बर्खास्त करने के लिए प्रधान और सचिव द्वारा प्रयोग किए गए अधिकार सहित सक्षम प्राधिकारी (बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) द्वारा 16.8.96 से पूर्वव्यापी प्रभाव से पुष्टि की गई, जिससे नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप एक अमान्य कार्य वैध हो गया। बर्खास्तगी आदेश सक्षम प्राधिकारी-बीओजी द्वारा नियमों में निर्धारित अनुसार पारित किया गया था और इस प्रकार, यह कानूनी और उचित था और बरकरार रखा गया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। [पैरा 35, 40, 42] [95-जी; 98-ई-एच; 99-ए, बी-सी]

परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता बनाम भारत संघ 1974 (1) एससीआर 304: (1973) 2 एससीसी 543; राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम पीपी सिंह एवं एक अन्य 2003 (1) एससीआर 593: (2003) 4 एससीसी 239; महाराष्ट्र राज्य खनन निगम बनाम सुनील (2006) 5 एससीसी 96 - संदर्भित किया गया ।

हार्टमैन बनाम होम्सबी 142 एमओ 368 44 एसडब्लू 242, 244 – संदर्भित किया गया।

प्रकरण कानून संदर्भ

1974 (1) एससीआर 304	संदर्भित किया गया	पैरा 37
2003 (1) एससीआर 593	संदर्भित किया गया	पैरा 38
(2006) 5 एससीसी 96	संदर्भित किया गया	पैरा 39

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5070/2008

रिट अपील संख्या 106/2004 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से दिनांक 17.11.2006 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से मनोज गोयल, शुवोदीप रॉय।

अंशुमान सिन्हा, इमरान आलम, रंजीत. बी, वर्तिका सहाय, कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप प्रतिवादीगण के लिये ।

न्यायालय का निर्णय अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। 1. यह अपील डब्ल्यू.ए. संख्या 106/2004 में गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 17.11.2006 के खिलाफ दायर की गई है।

2) इस अपील में शामिल मुद्दे की सराहना करने के लिए, जो एक संकीर्ण दायरे में निहित है, प्रासंगिक तथ्यों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3) अपीलकर्ता देश का एक प्रतिष्ठित तकनीकी शैक्षणिक संस्थान है। इसे असम राज्य के सिलचर में "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान" (इसके बाद "एनआईटी" के रूप में जाना जाता है) के रूप में जाना जाता है। 28.06.2002 तक, यह राज्य और केंद्र सरकार की समान भागीदारी में क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (इसके बाद "आरईसी" के रूप में संदर्भित) के रूप में कार्य कर रहा था। हालाँकि, 28.06.2002 को और उसके बाद, यह विशेष नियंत्रण के तहत पूर्ण स्वामित्व वाला केंद्रीय सरकारी शैक्षणिक संस्थान बन गया। केंद्र सरकार की देखरेख में और तदनुसार एनआईटी के रूप में संशोधित किया गया।

4) प्रतिवादी को मूल रूप से 17.07.1986 को तत्कालीन आरईसी द्वारा वारिस संस्थान में उप रजिस्ट्रार (लेखा) के रूप में नियुक्त किया गया था। कुछ वर्षों के बाद, निर्वाचित होने पर, प्रतिवादी को आरईसी के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया। हालाँकि, उसे उप रजिस्ट्रार (लेखा) का पद संभालने के लिए कहा गया था जब तक उक्त पद नियमित रूप से नहीं भरा जाता ।

5) वर्ष 1994-95 में, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार (लेखा) के रूप में कार्य करते हुए, प्रतिवादी ने कई गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं कीं। अनियमितताएं अवज्ञा के कृत्यों, संस्थान के काम को समाप्त करते समय कर्तव्यों की उपेक्षा, उच्च अधिकारियों से तथ्यों को छुपाना और संस्थान के धन का दुरुपयोग करना जिससे संस्थान को नुकसान उठाना पड़ रहा था आदि से संबंधित थीं।

6) आरईसी के प्रबंधन ने तदनुसार प्रतिवादी को असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 9 के तहत तीन कारण बताओ नोटिस/आरोप पत्र जारी किए, दो दिनांक 24;10;1994 (अनुलग्नक पी.1 एक साथ) को और एक 01.02.1995 (अनुलग्नक पी-3) को। प्रतिवादी द्वारा की गई अनियमितताओं/कदाचार का विवरण आरोप पत्र के साथ संलग्न किया गया था। प्रतिवादी को उपरोक्त आरोप पत्रों पर अपना लिखित उत्तर दाखिल करने के लिए कहा गया था। यदि वह ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया था।

7) इस मामले को तदनुसार 07.12.1994 को आयोजित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (संक्षेप में "बीओजी") की 66 वीं बैठक में एजेंडा आइटम संख्या 7 (ए) और 8 के रूप में शीर्षक के तहत रखा गया था - "हाल ही में एक नोट प्राप्त करने के लिए श्री पन्नालाल चौधरी, रजिस्ट्रार, जो उप रजिस्ट्रार (लेखा) का प्रभार भी संभाल रहे थे, द्वारा उत्पन्न वित्तीय गतिरोध और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाना" और दूसरा "आरईसी के खातों में ए.जी. ऑडिट द्वारा देखी गई अनियमितताओं के सुधार पर विचार करना "सिलचर"।

8) बीओजी ने उक्त बैठक में संदर्भ के तहत मामले पर चर्चा की और आरोपों की प्रकृति और उसके समर्थन में लगाए गए आरोपों के कारण इसे गंभीर माना। बीओजी ने

अब तक प्रतिवादी के खिलाफ प्रधान और सचिव द्वारा प्रस्तावित और शुरू की गई कार्रवाई को मंजूरी दे दी और अध्यक्ष, बीओजी के परामर्श से अगला अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया।

9) इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी सी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की नियमित विभागीय जांच करने के लिए प्रबंधन द्वारा तीन सदस्यों वाली एक जांच समिति का गठन किया गया। तीन सदस्यों में से एक डॉ. एस.के. दास - आरईसी सिलचर के मानविकी विभाग के प्रमुख को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि एप्लाइड मैकेनिक्स विभाग के प्रमुख श्री आर. गुप्ता और सीनियर ए.आई. लस्कर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग के व्याख्याता सदस्य थे। चूंकि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के थे, इसलिए बीओजी ने दिनांक 17.02.1995 के आदेश द्वारा प्रतिवादी को विभागीय जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया।

10) समिति ने तब प्रतिवादी को जांच में भाग लेने के लिए विभिन्न तिथियों जैसे 04.07.1995, 20.07.1995, 03.08.1995, 14.08.1995 और 27.12.1995 को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए लेकिन वह अपने ज्ञात कारणों के कारण उपस्थित होने में विफल रहा। प्रबंधन ने तदनुसार 14.08.1995 को आरोपों के समर्थन में चार गवाहों को परीक्षित कराया। इसके बाद, 27.12.1995 को प्रतिवादी ने समिति को एक पत्र भेजकर प्रार्थना की कि चूंकि उसने अपने निलंबन आदेश को अदालत में चुनौती दी है, इसलिए उसके खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही अदालती कार्यवाही के नतीजे की प्रतीक्षा में रोक दी जाए।

11) समिति ने प्रतिवादी द्वारा की गई प्रार्थना पर विचार किया और उसका विचार था कि किसी भी न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के अभाव में, प्रतिवादी द्वारा की गई प्रार्थना के अनुसार विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, समिति ने प्रतिवादी द्वारा की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया और प्रतिवादी

को एक और नोटिस जारी कर 10.01.1996 को समिति के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया। प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ और इसलिए जांच कार्यवाही 18.01.1996 के लिए स्थगित कर दी गई। प्रतिवादी को 18.01.1996 को उसकी उपस्थिति के लिए भेजे गए नोटिस में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि यदि प्रतिवादी उस तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो उसे कार्यवाही के बारे में कोई और नोटिस नहीं भेजा जाएगा। प्रतिवादी, नोटिस की तामील के बावजूद, 18.01.1996 को भी अनुपस्थित रहा। समिति ने तब प्रबंधन द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर अपनी कार्यवाही समाप्त की और 29.02.1996 को अपनी 16 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की (अनुलग्नक-पी-4), जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि 3 आरोप पत्रों में प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप साबित हुये।

12) 11.03.1996 को, समिति की रिपोर्ट को समिति के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए एजेंडा संख्या 6 और 24 के रूप में उनकी 68 वीं बैठक में बीओजी के समक्ष रखा गया था। बीओजी, रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, समिति के सभी निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और तदनुसार प्रतिवादी पर दंड लगाने का निर्णय लिया। बीओजी ने प्रधान और सचिव को कारण बताओ नोटिस तैयार करने और अध्यक्ष/बोर्ड की सलाह (अनुलग्नक-पी-5)के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी अधिकृत किया ।

13) तदनुसार, प्रतिवादी को दिनांक 29.02.1996 की जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ पंजीकृत डाक द्वारा 07.06.96 (अनुलग्नक-पी-6) को एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसमें प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त करने की सजा का प्रस्ताव किया गया था। कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के बाद भी प्रतिवादी ने कोई उत्तर दाखिल नहीं किया। तदनुसार प्रधान एवं सचिव ने अध्यक्ष को अपने पत्र दिनांक 01.07.1996 (अनुलग्नक-पी-7) द्वारा प्रतिवादी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत न करने के बारे में सूचित

किया। प्रधान एवं सचिव ने अपने आदेश दिनांक 16.08.1996 (अनुलग्नक-पी-8) द्वारा प्रतिवादी को आरईसी की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया।

14) इस मामले को प्रतिवादी की सेवाओं के संबंध में उचित आदेशों, यदि कोई हो, के लिए 22.08.1996 को आयोजित उनकी 69 वीं बैठक में आइटम नंबर 2 के रूप में बीओजी के समक्ष रखा गया था। बीओजी ने, स्पष्ट शब्दों में, मामले पर विचार-विमर्श करने के बाद पिछली बैठक के मिनटों को मंजूरी दे दी और प्रधान और सचिव द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी मंजूरी दे दी और तदनुसार उस संबंध में किए गए अनुपालन को नोट किया।

15) यह इन उपरोक्त तथ्यों के साथ है, जो (निर्विवाद रूप से, प्रतिवादी, दिनांक 16.08.1996 के बर्खास्तगी आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। रिट याचिका में बर्खास्तगी आदेश को चुनौती अनिवार्य रूप से एक आधार पर थी, अर्थात्, जिस प्राधिकारी ने बर्खास्तगी आदेश पारित किया था, उसके पास इसे पारित करने की कोई शक्ति नहीं थी और इसलिए यह अवैध था और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि नियमों के अनुसार बर्खास्तगी आदेश पारित करने की शक्ति बीओजी में निहित है और इसलिए केवल बीओजी ही ऐसा आदेश पारित कर सकता है। यह बताया गया कि चूंकि बर्खास्तगी आदेश प्रधान और सचिव द्वारा पारित किया गया था, जिनके पास नियमों के तहत ऐसा आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए बर्खास्तगी आदेश कानूनन खराब था। यह भी तर्क दिया गया कि भले ही यह मान लिया जाए कि बीओजी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रतिवादी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रधान और सचिव के पक्ष में अपनी शक्तियां सौंप दी हैं, फिर भी इस संबंध में बीओजी द्वारा पारित प्रस्तावों को पढ़ने मात्र से यह पता चलता है कि प्रधान और सचिव को

ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई या/और सौंपी गई ताकि उन्हें प्रतिवादी की बर्खास्तगी आदेश पारित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

16) अपीलकर्ता (रिट याचिका में प्रतिवादी के रूप में) ने रिट याचिका का विरोध करते हुए अपनी कार्रवाई का बचाव किया, जिसकी परिणति प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्तगी के रूप में हुई और तर्क दिया कि इसे नियमों के अनुसार पारित किया गया था। अपीलकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी के खिलाफ प्रस्तावित, शुरू की गई और अंततः की गई पूरी कार्रवाई, जिसके परिणामस्वरूप उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, बीओजी द्वारा लिया गया था और बाद में विभिन्न तिथियों पर आयोजित अपनी बैठकों में बीओजी द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसलिए यह गलत था। प्रतिवादी का तर्क है कि बर्खास्तगी आदेश बीओजी द्वारा पारित नहीं किया गया था, बल्कि प्रधान और सचिव द्वारा पारित किया गया था। यह बताया गया कि प्रधान और सचिव को भी बीओजी द्वारा अध्यक्ष, बीओजी के परामर्श से प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया था, जो उन्होंने उन्हें सौंपी गई शक्ति के अनुसार किया और बाद में बीओजी से इसकी मंजूरी मांगी। अंततः यह तर्क दिया गया कि जब बीओजी ने 22.08.1996 को आयोजित अपनी अंतिम बैठक में बर्खास्तगी आदेश पारित करने सहित पूरी कार्रवाई को मंजूरी दे दी, तो प्रधान और सचिव द्वारा की गई सभी पिछली कार्रवाइयों को बीओजी द्वारा उनके किये जाने की दिनांक से अनुमोदित किया गया और इस प्रकार वे कानूनी और उचित बन गए। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ शुरू की गई संपूर्ण विभागीय कार्यवाही का भी बचाव करते हुए तर्क दिया कि विभागीय कार्यवाही नियमों में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करके और प्रतिवादी को बचाव का पूरा अवसर देकर कानून के अनुसार आयोजित की गई थी और इसलिए कार्यवाही में कोई दोष नहीं देखा जा सकता है।

17) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रिट कोर्ट (एकल न्यायाधीश) ने प्रतिवादी की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और 16.08.1996 के बर्खास्तगी आदेश को इस संक्षिप्त आधार पर रद्द कर दिया कि चूंकि सक्षम प्राधिकारी ने नियमों में निर्धारित बर्खास्तगी आदेश पारित नहीं किया था, यानि कि बीओजी, जबकि इसे प्रधान और सचिव द्वारा पारित किया गया था, जिनके पास नियमों के तहत इस तरह के बर्खास्तगी आदेश को पारित करने का कोई अधिकार नहीं था और इसलिए इसे नियमों के खिलाफ होने के कारण रद्द किया जा सकता था। तदनुसार, रिट अदालत ने दिनांक 16.08.1996 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता को सभी परिणामी लाभ देकर प्रतिवादी को उनकी सेवाओं में बहाल करने का निर्देश दिया गया था।

18) उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। आक्षेपित आदेश द्वारा, डिवीजन बेंच ने एकल न्यायाधीश (रिट कोर्ट) द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमति जताते हुए अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की।

19) अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील श्री मनोज गोयल और प्रतिवादी संख्या 1 के लिए विद्वान वकील श्री अंशुमन सिन्हा को सुना।

20) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मनोज गोयल ने रिट अदालत और अपीलीय अदालत द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि नीचे दी गई दोनों अदालतों ने प्रतिवादी की रिट याचिका को अनुमति देने और 16.08.1996 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने में गलती की।

21) सबसे पहले, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पूरी विभागीय कार्यवाही में कोई गलती नहीं देखी जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः प्रतिवादी को सेवाओं से बाहर कर दिया गया क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार सख्ती से आयोजित किया गया था।

22) दूसरे स्थान पर, उनका तर्क यह था कि प्रधान और सचिव को बीओजी द्वारा विभागीय कार्यवाही शुरू करने और प्रतिवादी के खिलाफ बीओजी के अध्यक्ष के परामर्श से उचित कार्रवाई करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया था। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने समय-समय पर बीओजी द्वारा पारित विभिन्न प्रस्तावों और विशेष रूप से दिनांक 07.12.1994, 08.06.1995, 11.03.1996 और 22.08.1996 के प्रस्तावों पर भरोसा जताया।

23) तीसरे स्थान पर, उन्होंने तर्क दिया कि बीओजी विभागीय कार्यवाही के हर चरण में सभी विचार-विमर्श में शामिल था जैसा कि बीओजी की बैठकों के मिनटों से स्पष्ट होगा और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि बीओजी ने इस पर विचार नहीं किया। किसी भी निर्णय या उसे कार्यवाही की जानकारी नहीं थी या उसने प्रधान और सचिव द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ की गई कार्रवाई को मंजूरी नहीं दी थी।

24) चौथे स्थान पर, यह तर्क दिया गया कि विचाराधीन संपूर्ण कार्रवाई को बीओजी द्वारा 22.08.1996 को आयोजित अपनी अंतिम बैठक में अनुमोदित या/और अनुसमर्थित किया गया था, जो भी तथाकथित दोष थे, भले ही 16.8.96 को बर्खास्तगी आदेश पारित करने सहित विभागीय कार्यवाही में मौजूद था, लेकिन 22.8.96 को आयोजित उनकी बैठक में बीओजी द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी और इसलिए कार्यवाही में कोई गलती नहीं देखी जा सकती है।

25) इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष का समर्थन किया और तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है। तब विद्वान् वकील ने दोनों न्यायालयों द्वारा दिए गए कारणों के समर्थन में अपनी दलीलों को विस्तार से बताया।

26) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए सभी तर्कों में बल पाते हैं। ऐसा हम निम्नलिखित कारणों से कहते हैं:

27) दहलीज पर; यह देखा गया है कि रिट याचिका में, प्रतिवादी ने योग्यता के आधार पर बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देने के लिए कई आधार लिए थे: हालाँकि, रिट अदालत के आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि रिट याचिकाकर्ता ने किसी भी आधार पर जोर नहीं दिया था। रिट याचिका पर मुकदमा चलाते समय उन्होंने एकमात्र आधार यह बताया कि बर्खास्तगी का आदेश एनआईटी के प्रिंसिपल और सचिव द्वारा पारित किया गया था, जिनके पास इस तरह के आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। चूंकि प्रतिवादी को बर्खास्त करने का अधिकार नियमों के तहत एनआईटी के बीओजी में निहित था और इसलिए बर्खास्तगी आदेश कानून की दृष्टि से खराब था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष उपरोक्त उल्लिखित को छोड़कर किसी भी आधार पर जोर नहीं दिया, हमें किसी भी आधार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय को एकमात्र मुद्दा यह तय करने के लिए बुलाया गया था कि क्या प्रतिवादी को सेवा से हटाने का कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया था?

28) जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि दिनांक 16.08.1996 का बर्खास्तगी का विवादित आदेश वास्तव में सही था। प्रधान एवं सचिव द्वारा पारित किया गया, जिनके पास नियमों के

तहत ऐसा आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। यह माना गया कि नियमों के तहत बर्खास्तगी आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी बीओजी था। तदनुसार उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को सभी परिणामी सेवा लाभ देने के निर्देश के साथ बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील में, खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और तदनुसार अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया, जिससे अपीलकर्ता (प्रबंधन) द्वारा इस अपील को दाखिल करने का मौका मिला।

29) इससे पहले कि हम प्रस्तुतियों की सराहना करें, बीओजी की बैठकों के प्रासंगिक उद्धरणों को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा ताकि यह दिखाया जा सके कि बीओजी द्वारा प्रतिवादी के मुद्दे को कैसे निपटाया गया था:

(1)

<u>07.12.1994 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त</u>

"मद-7(ए): श्री पन्नालाल चौधरी, रजिस्ट्रार, जो उप रजिस्ट्रार (लेखा) का प्रभार भी संभाल रहे थे, द्वारा हाल ही में पैदा किए गए वित्तीय गतिरोध का एक नोट प्राप्त करने और उपचारात्मक सुझाव देने के लिए भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के उपाय:

बोर्ड ने वित्तीय गतिरोध के संबंध में माननीय अध्यक्ष, बीओजी की सलाह पर प्रधान और सचिव द्वारा की गई कार्रवाई को मंजूरी दे दी।

इसके अलावा, अवज्ञा, कर्तव्य में लापरवाही, तथ्यों को दबाने आदि के विभिन्न आरोपों पर चर्चा करते हुए प्रधान और सचिव द्वारा श्री पन्नालाल चौधरी, रजिस्ट्रार, जो उप रजिस्ट्रार (लेखा) का प्रभार भी संभाल रहे थे, को आरोप पत्र सौंपे गए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मामले को पूरी गंभीरता से लिया और प्रिंसिपल और सचिव को माननीय

अध्यक्ष, बीओजी, आरईसी सिलचर के परामर्श से आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आवश्यक कानूनी सलाह लेने का निर्देश दिया।

"आइटम-8: रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, सिलचर के खातों में ए.जी. ऑडिट द्वारा देखी गई अनियमितताओं के सुधार पर विचार करना।

बोर्ड ने ए.जी. ऑडिट और प्रधान एवं सचिव, बीओजी द्वारा उजागर की गई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं की जांच की और पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया और प्रिंसिपल और सचिव को कानूनी सलाह लेने और रजिस्ट्रार श्री पन्नालाल चौधरी, जो उप रजिस्ट्रार (लेखा) का प्रभार भी संभाल रहे थे, के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

बोर्ड ने प्रिंसिपल और सचिव, बीओजी को माननीय अध्यक्ष, बीओजी के परामर्श से अगला अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया।

(2)

<u>08.06.1995 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त</u>

मद 6: श्री पन्नालाल चौधरी, रजिस्ट्रार (निलंबनाधीन) के मामले पर निर्णय लेना।

श्री पन्नालाल चौधरी, रजिस्ट्रार को सचिव, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा आवश्यक कानूनी सलाह के साथ-साथ माननीय अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा लिखित निर्देश प्राप्त करने के बाद 17.02.1995 को निलंबित कर दिया गया था।

माननीय बोर्ड ने अपनी 66 वीं बैठक में आइटम नंबर 7 (ए) के तहत कर्तव्य की अवहेलना, तथ्यों को दबाने आदि के विभिन्न प्रशासनिक आरोपों पर चर्चा की और तदनुसार श्री चौधरी को आरोप पत्र सौंपे गए। इसके बाद बोर्ड ने प्रिंसिपल और सचिव को माननीय अध्यक्ष, बोर्ड ओ गवर्नर्स के परामर्श से आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई

के लिए आवश्यक कानूनी सलाह लेने का निर्देश दिया और बोर्ड ने उसी बैठक में मद संख्या 8 में एजी ऑडिट और प्रधान और सचिव द्वारा उजागर की गई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच की। बोर्ड ने पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया और सचिव को आगे की कानूनी सलाह लेने और श्री चौधरी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

प्रिंसिपल और सचिव ने तदनुसार कॉलेज द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं से सभी आवश्यक कानूनी सलाह ली और विभागीय कार्यवाही के उद्देश्य से निम्नलिखित सदस्यों के साथ 6 मई, 1995 को एक जांच बोर्ड का गठन किया गया: -

1. पीठासीन अधिकारी: डॉ. एस.के. दास

2. सदस्य : i) डॉ. आर. गुप्ता

: ii) प्रो. ए.आई. लस्कर

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी: श्री सुदीप्त कुमार भट्टाचार्य

[हालाँकि, वर्तमान में एक नए प्रस्तुतिकरण अधिकारी श्री एफ.ए. तालुकदार, व्याख्याता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग श्री सुदीप्त कुमार भट्टाचार्जी के रूप में नियुक्त किया गया है ने प्रस्तुतिकरण अधिकारी के रूप में बने रहने में अपनी असमर्थता बताई है क्योंकि उन्होंने चिकित्सा आधार पर छुट्टी के लिए आवेदन किया है।]

जांच बोर्ड ने अपना निर्धारित कार्य पहले ही पूरा कर लिया है और बोर्ड की रिपोर्ट को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए मेज पर रखा जाएगा।"

(3)

11.03.1996 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

"आइटम -6: श्री पन्नालाल चौधरी रजिस्ट्रार (निलंबन के तहत) के मामले पर निर्णय लेने के लिए।

जांच बोर्ड की रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष रखी गई और विस्तृत चर्चा के बाद, बोर्ड ने प्रिंसिपल और सचिव को बोर्ड की ओर से श्री पन्नालाल चौधरी, रजिस्ट्रार (निलंबन के तहत) को सजा लागू करने के लिये कारण बताओ नोटिस का मसौदा तैयार करने के लिए अधिकृत किया और उसकी एक प्रति मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ भेजने को कि वे अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, 21 दिनों के भीतर सूचित करें। बोर्ड ने प्रधान और सचिव को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उपरोक्त अवधि की समाप्ति के बाद कारण बताओ नोटिस का मसौदा प्रस्तुत करने और बोर्ड द्वारा श्री पन्नालाल चौधरी, रजिस्ट्रार (निलंबन के तहत) को और अध्यक्ष/बोर्ड की सलाह के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उक्त कारण बताओ नोटिस की तामील के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष को कानूनी सलाह लेने के लिए भी अधिकृत किया है।"

"आइटम-24: उप रजिस्ट्रार (लेखा) के रूप में श्री पन्नालाल चौधरी द्वारा कॉलेज के पैसे के दुरुपयोग पर निर्णय लेना।

बोर्ड ने मद संख्या 6 के संबंध में इस मद पर चर्चा की और प्रमुख सचिव को तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया।"

(4)

22.08.1996 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त"

"आइटम-2: पिछली बैठक के प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई और प्रगति पर एक नोट प्राप्त करना।

मद-6 बी68/96 के अंतर्गत:

बोर्ड के संकल्प और निर्देश के अनुसरण में कार्रवाई की गई और श्री पन्नालाल चौधरी, रजिस्ट्रार (निलंबन के तहत) को 16.8.1996 को बर्खास्तगी आदेश जारी किया गया था और उनका नाम क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सिलचर समाज की ताकत से काट दिया गया था। बोर्ड ने की गई कार्रवाई के अनुपालन को नोट किया।

बोर्ड ने आइटम नंबर 7, 8, 10, 15, 24 और 25 के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी नोट किया और उसे मंजूरी दे दी।"

30) बीओजी द्वारा पारित उपरोक्त चार प्रस्तावों को बिना किसी अनिश्चित शब्दों के साथ पढ़ने से पता चलता है कि बीओजी ने शुरुआत से ही अपनी विभिन्न बैठकों में प्रतिवादी के मामले की निगरानी की, निपटाया और अंततः निर्णय लिया और इससे निपटने के लिए प्रधान और सचिव को भी अधिकृत किया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के परामर्श से और उचित आदेश पारित करके आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। यह भी स्पष्ट है कि 22.08.1996 को आयोजित अंतिम बैठक में, बीओजी ने 11.03.1996 को आयोजित पिछली 68 वीं बैठक में पारित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसमें आइटम नंबर 6 और 24 पर प्रतिवादी के मामले से निपटा गया था।

31) हमारे सुविचारित विचार में, आइटम नंबर 6 में अभिव्यक्ति "प्राधिकरण" और "अध्यक्ष की सलाह के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए" और अंत में, संकल्प दिनांक 11.03.1996 में आइटम नंबर 24 में अभिव्यक्ति "तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए" इतने विस्तृत थे कि प्रधान और सचिव को अवसर पड़ने पर बर्खास्तगी आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की जा सके।

32) जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने सही तर्क दिया था, प्रधान और सचिव को उचित आदेश पारित करने के लिए अधिकृत करने वाले प्रस्तावों में "प्रतिवादी को खारिज करने के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि उस समय, प्रतिवादी के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन थी। इसलिए, उस समय यह ज्ञात नहीं था कि विभागीय कार्यवाही का नतीजा क्या होगा और दूसरे, विभागीय जांच शुरू होने से पहले संकल्प में इस तरह की अभिव्यक्ति का उपयोग प्रतिवादी के खिलाफ मुद्दे को पूर्वाग्रहित करने के रूप में माना जा सकता था, जिससे अस्तित्व का संकेत मिलता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्यों का प्रतिवादी के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया और अंत में जैसा कि ऊपर कहा गया है, संकल्प में इस्तेमाल की गई तीन अभिव्यक्तियाँ प्रधान और सचिव को उचित आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करती हैं, जिसमें विभागीय जांच के नतीजे के आधार पर और बीओजी द्वारा अंतिम अनुमोदन के अधीन प्रतिवादी के खिलाफ नियमों में निर्धारित बर्खास्तगी की सजा लगाने का आदेश भी शामिल है। वास्तव में संकल्प में इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति "और अध्यक्ष/बोर्ड की सलाह के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना" और "जरूरतमंदों को करना" प्रतिवादी के खिलाफ विचाराधीन इच्छित कार्रवाई करने के लिए संकल्प में बहुत उपयुक्त शब्द थे।

33) उपरोक्त चर्चा के आलोक में और संकल्पों की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत होना मुश्किल है कि बीओजी ने बर्खास्तगी आदेश पारित नहीं किया था, बल्कि इसे प्रधान और सचिव द्वारा पारित किया गया था। दूसरे शब्दों में, चार प्रस्तावों की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बर्खास्तगी आदेश दिनांक 16.08.1996 बीओजी द्वारा पारित किया गया था और प्रधान और सचिव ने केवल बीओजी के लिए और उसकी ओर से आदेश पर दिनांक 11.03.1996 के प्रस्ताव के माध्यम से बीओजी द्वारा उनके पक्ष में किए गए प्राधिकरण के बल पर हस्ताक्षर किए थे।

34) इसके अलावा, "अनुमोदन" से संबंधित कानून को लागू करके विचाराधीन मुद्दे की एक और कोण से जांच की जा सकती है, जिस पर उच्च न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया।

35) अभिव्यक्ति "अनुमोदन" का अर्थ है "पहले से किए गए कार्य को वैध बनाना"। यह सिद्धांत लैटिन कहावत "रतिहाबिटियो मैंडेटो एइक्विपरेटुर" से लिया गया है, जिसका अर्थ है "किसी अधिनियम का बाद का अनुसमर्थन ऐसे कार्य को करने के लिए पूर्व प्राधिकारी के बराबर है।" यह इस कारण से है; अनुसमर्थन एक अमान्य कार्य मानता है, जिसे पूर्वव्यापी रूप से मान्य किया जाता है।

36) अभिव्यक्ति "अनुमोदन" को संक्षेप में एक पुराने मामले, हार्टमैन बनाम हॉर्स्बी ने 142 एमओ 368 44 एसडब्ल्यू 242, 244 में रिपोर्टेड अंग्रेजी न्यायालय द्वारा निम्नानुसार पारिभाषित किया:

> "'अनुमोदन' उस कार्य, शब्द या आचरण द्वारा अनुमोदन है, जिसका प्रयास (सिद्धि का) किया गया था, लेकिन जो पहली बार में अनुचित या अनधिकृत तरीके से किया गया था।"

37) इस न्यायालय द्वारा परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता बनाम भारत संघ यू.ओ.आई (1973) 2 एससीसी 543 में अनुसमर्थन का कानून लागू किया गया था। उस मामले में, निदेशक मंडल के अध्यक्ष ने एक बैठक में बोर्ड द्वारा लिए गए एक प्रस्ताव के अनुसार एक कंपनी के महाप्रबंधक की सेवाओं को समाप्त कर दिया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि बैठक अनुचित तरीके से आयोजित की गई थी और परिणामस्वरूप महाप्रबंधक की सेवाओं को समाप्त करने के लिए उक्त बैठक में पारित प्रस्ताव अमान्य था। हालाँकि, इसके बाद निदेशक मंडल ने अगली बैठक बुलाई और इस बैठक में

पिछले प्रस्ताव की पुष्टि की, जो अनुचित बैठक में पारित किया गया था। इन तथ्यों पर, न्यायालय ने कहा,

> "भले ही यह मान लिया जाए कि अध्यक्ष द्वारा अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने वाला टेलीग्राम और पत्र उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए 16-12-1953 को पारित निदेशक मंडल के अवैध प्रस्ताव के अनुसरण में था, यह इसका पालन नहीं करेगा निदेशक मंडल की नियमित रूप से बुलाई जाने वाली बैठक में अध्यक्ष की कार्रवाई की पुष्टि नहीं की जा सकी। मुद्दा यह है कि यह मानते हुए भी कि अध्यक्ष अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं था, वह कंपनी की ओर से ऐसे करने के लिये कार्य कर रहा था क्योंकि, उसने अवैध प्रस्ताव के अनुसरण में कार्य करने का दावा किया था। इसलिए, उस कार्रवाई की पुष्टि के लिए निदेशक मंडल की नियमित रूप से गठित बैठक का विकल्प खुला था, जो कि अनधिकृत होते हुए भी कंपनी की तरफ से किया गया था। अनुसमर्थन हमेशा अनुसमर्थित अधिनियम की तारीख से संबंधित होगा और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि अपीलकर्ता की सेवाएं 17-12-1953 को वैध रूप से समाप्त कर दी गई थीं।"

38) इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय बनाम पी.पी. सिंह एवं अन्य. (2003) 4 एससीसी 239 न्यायिक मामले में अनुमोदित किया गया था।

39) अनुसमर्थन के कानून के उपरोक्त सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य खनन निगम बनाम सुनील (2006) 5 एससीसी 96 में फिर से लागू किया गया था। इस मामले में, प्रतिवादी अपीलकर्ता निगम का कर्मचारी था। विभागीय जांच के परिणामस्वरूप, उन्हें अपीलकर्ता के प्रबंध निदेशक द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। रिट याचिका

की सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता निगम के निदेशक मंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें प्रबंध निदेशक की विवादित कार्रवाई की पुष्टि की गई और उन्हें अधिकतम वेतन ग्रेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। रुपये 4700 /- प्रतिमाह से अधिक नहीं था। इससे पहले, मैं प्रबंध निदेशक के पास केवल उन पदों के संबंध में शक्तियां थीं जहां अधिकतम वेतन रुपये 1900/-प्रतिमाह से अधिक नहीं था। प्रासंगिक समय पर प्रतिवादी रुपये 1800/- प्रतिमाह से अधिक प्राप्त कर रहा था। इसलिए, प्रासंगिक समय पर, प्रबंध निदेशक प्रतिवादी को बर्खास्त करने में अक्षम थे। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश को अवैध ठहराया। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उक्त दोष को बाद में निदेशक मंडल के संकल्प द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया और परिणामी राहत दी। इसके बाद अपीलकर्ता ने विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर की। न्यायमूर्ति रुमा पाल ने तीन जजों की पीठ की ओर से बोलते हुए अपील को स्वीकार करते हुए और अदालत के आदेश को इस प्रकार खारिज कर दिया:

> "उच्च न्यायालय ने सही ढंग से माना कि कानूनी रूप से अक्षम प्राधिकारी द्वारा कियागया कार्य अमान्य है। लेकिन यह मानना पूरी तरह से गलत था कि इस तरह के अमान्य कार्य को बाद में सक्षम प्राधिकारी के अनुसमर्थन द्वारा "सुधार" नहीं किया जा सकता है। परिभाषा के अनुसार अनुसमर्थन का अर्थ पहले से किए गए कार्य को वैध बनाना है। यह सिद्धांत लैटिन कहावत रतिहैबिटियो मैंडेटो एक्वीपारटूर से लिया गया है, अर्थात्, "किसी अधिनियम का बाद का अनुसमर्थन ऐसे कार्य को करने के लिए पूर्व प्राधिकारी के बराबर है।" इसलिए, अनुसमर्थन एक अमान्य कार्य मानता है जिसे पूर्वव्यापी रूप से मान्य किया जाता है।"
>
> "वर्तमान मामले में, प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त करने के प्रबंध निदेशक के आदेश को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार्य रूप से अनुमोदित किया गया था, इसमें

निर्विवाद रूप से प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति थी। चूंकि प्रबंध निदेशक के आदेश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था ऐसा अनुसमर्थन आदेश की तारीख से संबंधित है और इसे मान्य किया गया है।"

40) मौजूदा तथ्यों पर अनुसमर्थन के उपरोक्त कानून को लागू करना, भले ही हम तर्क के लिए मान लें कि बर्खास्तगी का आदेश दिनांक 16.08.1996 को प्रधान और सचिव द्वारा पारित किया गया था, जिनके पास इस तरह के आदेश को पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। नियमों के अनुसार और न ही बीओजी द्वारा इस तरह के आदेश पारित करने के लिए उनके पक्ष में कोई प्राधिकरण दिया गया था, फिर भी हमारे विचार में जब बीओजी ने 22.08.1996 को आयोजित अपनी बैठक में प्रतिवादी के बर्खास्तगी आदेश दिनांक 16.08.1996 को पारित करने में प्रधान और सचिव की पिछली कार्रवाइयों को मंजूरी दे दी थी, कार्यवाही में प्रतिवादी द्वारा की गई सभी अनियमितताओं की शिकायत की गई, जिसमें प्रधान और सचिव द्वारा उसे बर्खास्त करने के लिए प्रयोग किए गए अधिकार भी शामिल थे, सक्षम प्राधिकारी (बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) द्वारा स्वयं 16.8.1996 से पूर्वव्यापी प्रभाव से पुष्टि की गई, जिससे नियमो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप एक अमान्य कार्य वैध हो जाता है।

41) ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादी की शिकायत कि बर्खास्तगी आदेश सक्षम प्राधिकारी, यानी बीओजी द्वारा पारित नहीं किया गया था, अब जीवित नहीं है।

42) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असहमत हैं और तदनुसार मानते हैं कि बर्खास्तगी आदेश दिनांक 16.08.1996 को सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् बीओजी द्वारा नियमों में निर्धारित अनुसार पारित किया गया था और इसलिए यह कानूनी और उचित था। तदनुसार इसे कायम रखा जाता है।

43) जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी द्वारा रिट याचिका में और साथ ही अपीलकर्ता की इंट्रा-कोर्ट अपील में अन्य आधारों पर बर्खास्तगी आदेश की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाने के लिए क्रॉस आपत्ति दर्ज करके किसी अन्य बिंदु पर आग्रह नहीं किया गया था हमने फैसला कर लिया है। इसलिए, किसी अन्य प्रश्न पर जाना आवश्यक नहीं है।

44) पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, अपील सफल होती है और इसे स्वीकार किया जाता है। विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की जाती है। कोई लागत नहीं।

निधि जैन अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।